प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

31.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के चार अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी मशीनें स्थापित की गई हैं। इन मशीनों की खरीद ई–टेंडरिंग के माध्यम से की गई है और अस्पताल स्टाफ को इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल, केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार और सुरेंद्र शौरी के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 20 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोबोटिक सर्जरी को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए प्रयासरत है और गरीब वर्ग के मरीजों को राहत देने के लिए सर्जरी पर करीब 70 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जबकि स्पेशल वार्ड लेने वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी और एम.आर.आई. सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर और आयुष्मान योजना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा का लाभ देने पर सरकार विचार करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रोबोटिक सर्जरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऑपरेशन पर करीब एक लाख रुपये खर्च आने से यह सुविधा सीमित वर्ग तक ही रह सकती है।

मुख्यमंत्री वक्तव्य

हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमाओं में एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने यथास्थिति बहाल करने का ऐलान किया है। विधानसभा में आज एक विशेष वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एंट्री टैक्स में किसी प्रकार की बड़ी वृद्धि नहीं की है, बल्कि केवल विभिन्न श्रेणियों को रैशनलाइज किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करने की कोशिश की गई है लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रदेश में टोल टैक्स की दरों में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ श्रेणियों में मामूली संशोधन किया गया है, जो सीमित संख्या में आने वाली भारी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन वाहनों पर लागू होता है।

शून्यकाल

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि शून्यकाल के दौरान विधायकों की तरफ से उठाए गए मामलों की निगरानी के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य वे स्वयं होंगे। विधानसभा में आज शून्यकाल में विधायक रणधीर शर्मा द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार शून्यकाल को गंभीरता से नहीं ले रही है और अभी तक उनके द्वारा उठाए गए 10 विषयों पर सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है।

जयराम ठाकुर

चैस्टर हिल प्रोजैक्ट्स मामले में अधिकारियों में छिड़ी आपसी जंग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं और उन्होंने अपनी सफाई में कुछ अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर चुप्पी साधी है जबकि सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने सदन में भी दो बार धारा 118 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।

जनगणना 2027

केन्द्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना दो

चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घर–घर जाकर सूचीकरण और स्व–गणना की प्रक्रिया पूरी होगी। यह चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा।

…………………………………………